www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 172 नागपुर, शुक्रवार, 19 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

चेन्नई में कपड़े की दुकान से 45 करोड़ के पुराने नोट बरामद

चेन्नई

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुलिस ने एक शख्स के पास से 45 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शख्स एक वकील व बिजनेसमैन है। 45 करोड़ रुपए मूल्य के 1,000 और 500 रुपए के पुराने नोट कार्टन बॉक्स में रखे गए थे, जो यहां कोडमबक्कम के जकारिया कॉलोनी स्थित एक घर में चल रही दुकान से बरामद किए गए। घर में ही कपड़े की एक दुकान है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मालिक को पूछताछ के लिए कोडमबक्कम पुलिस थाने लाया गया। उसने दावा किया कि किसी और शख्स ने उसे ये रुपए सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। इस बारे में इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

थाणे में भी एक करोड़ के पुराने नोट जब्त, तीन गिरफ्तार

थाणे में भी पुलिस ने तीन लोगों के पास से करीब एक करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद मंगलवार देर रात एक कार को रोक कर पूछताछ की तो तीन लोगों के पास से एक करोड़ रुपए मूल्य के 1,000-500 रुपए के पुराने नोट बरामद हुए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पता लगा रही है कि ये पुराने नोट उनके पास कहां से आए। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है।

अन्ना ने वरुण गांधी से कहा, राइट टु रिजेक्ट के लिए भी करें प्रयास

मुंबई

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने भाजपा के युवा नेता वरुण गांधी को पत्र लिखकर राइट टु रिकॉल बिल पर उनका अभिनंदन किया है। साथ ही उनसे राइट टु रिजेक्ट कानून के लिए भी प्रयास करने का आह्वान किया है।

अन्ना ने अपने पत्र में वरुण से कहा है कि आप राईट टू रिकॉल का कानून बनवाने के लिए संसद में एक बिल पेश करना चाहते हैं। इसके लिए देश की जनता की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। क्योंकि ऐसे कानून से देश में सही लोकतंत्र आने में मदद मिलेगी। अन्ना के अनुसार, आजादी के बाद 69 साल में ऐसा बिल किसी भी सांसद ने पेश नहीं किया। हम 2008 से लगातार ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं।

इस बिल में राइट टू रिकॉल की सोच के साथ-साथ राईट टू रिजेक्ट की सोच भी जरूरी है। आज देश में ज्यादातर राजनीतिक दल सत्ता पाने की स्पर्धा में लगे हैं। सत्ता के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा के कारण उम्मीदवार के गुंडा, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, व्यभिचारी, गुनहगार होते हुए भी पार्टी की ओर से टिकट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं को उन उम्मीदवारों को रिजेक्ट (नकारने) करने का अधिकार होना चाहिए। अन्ना के अनुसार, यदि मतदाता मतपत्र या मशीन पर बने नापसंदगी के बटन पर सर्वाधिक मत दे दें तो उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद हो जाना चाहिए।

जाधव मामले में पाकिस्तान को झटका

आइसीजे ने लगाई फांसी पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली

पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में ले जाने का भारत का फैसला सही साबित हुआ है। आइसीजे ने अपने अंतरिम फैसले में पाकिस्तान को आदेश दिया है कि वह इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक जाधव को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा कर रखे।

आइसीजे के न्यायाधीश रोनी अब्राहम ने कहा है कि अभी जैसी स्थिति है वैसी पाकिस्तान को बना कर रखनी होगी। आइसीजे ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उसे इस तरह के मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने यह भी माना है कि जेल में बंद जाधव तक भारतीय उच्चायोग की पहुंच नहीं दी गई। न्यायालय ने भारत के इस तर्क को भी स्वीकार किया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने और फैसला लेने की जरुरत है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि वह जाधव के मामले में आईसीजे के फैसले का इंतजार करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा- पहली कामयाबी मिली

कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर अंतरराष्ट्रीय अदालत की तरफ से लगाई गई अंतरिम रोक को भारतीय विदेश मंत्रालय ने जाधव को बचाने की दिशा में पहली कामयाबी बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने जाधव की फांसी रुकने के आइसीजे के आए फैसले के बाद कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने कहा कि आइसीजे के फैसले से आज पूरा देश राहत महसूस कर रहा है।

यह पहला मामला है जब भारत ने दूसरे जेल में बंद अपने किसी नागरिक को रिहा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दरवाजे तक

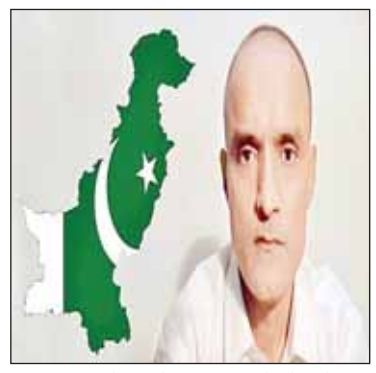

पहुंचा है। इसके पहले पाकिस्तान के जेल में बंद कई भारतीय नागरिकों को सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाये जाने की वजह वर्षों तक कैद में रहना पड़ा है।

सरबजीत सिंह का मामला सभी के सामने है, लेकिन भारत ने इस मामले को आइसीजे में ले जा कर पाकिस्तान के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो यह कहता रहा है कि जाधव के मामले में पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। पाकिस्तान सेना की तरफ से चलाये गये मुकदमे में उसे गलत साबित करने में भारत सफल रहा है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

पाक की घर में किरकिरी, विशेषज्ञ बोले- अधूरी थी तैयारी

कुलभषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत हुई तो वहीं पाकिस्तान को जोरदार झटका लगा है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के अंतरिम फैसले के बाद पाकिस्तान अपने घर में ही घिरता नजर आ रहा है। इस फैसले के बाद भारत के लोगों में जहां खुशी की लहर है तो वहीं पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं। पाकिस्तान के नागरिक अब अपने ही वकीलों को कोस रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी विश्लेषक इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि आइसीजे के पास जाधव की फांसी पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद समीक्षकों का कहना है कि हमारे वकीलों की बहस काफी कमजोर और हानिकारक थी। पाकिस्तान समाचार डॉन न्यूज के साथ बातचीत में रिटायर्ड जस्टिस शेख उस्मानी ने कहा कि ये फैसला चेतावनी है क्योंकि आईसीजे के पास इसका अधिकार नहीं है।

पाकिस्तान ने इस बहस में शामिल होकर गलती की है। उन्होंने अपने पैरों में खुद गोली मारी है। उन्होंने कहा कि जब तक आईसीजे इस पर निर्णय नहीं ले लेती तब तक ये केस पाकिस्तान में जारी रहेगा। लेकिन स्टे ऑर्डर के बाद जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती।

गोवा: फुट ओवरब्रिज टूटने से 50 लोग नदी में गिरे, दो की मौत, 30 लापता

पणजी

दक्षिण गोवा के कुरकोरम में फुट ओवर ब्रिज ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। पुल टूटने के कारण 50 लोग नदी में गिर गए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लापता बताए जा रहे हैं।

कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस एक शख्स को पुल से नदी में छलांग लगाने से बचा रही थी।

बताया जा रहा है कि ये पुल पुर्तगाल के शासन के समय का था। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोताखोरों ने एक शव बरामद कर लिया गया है।

पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन

नई दिल्ली

पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का गुरुवार सुबह दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दवे की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। अनिल माधव दवे 61 साल के थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त और एक बहुत ही सम्मानित सहयोगी पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के अचानक निधन से बिल्कुल चौंक गया हूं। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने बताया कि वह कल शाम देर तक अनिल माधव दवे जी के साथ थे और प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे।

नहीं रहीं बॉलीवुड की 'मां' रीमा लागू

मुंबई

मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और कल हो न हो जैसी फिल्मों में मां के शानदार किरदार के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रीमा लागू का गुरुवार तड़के मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 59 वर्ष की थीं। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक राम नारायण ने बताया कि रीमा को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा, हम उनके परिवार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद उनके स्वास्थ्य संबंधी एक रिपोर्ट जारी करेंगे। रीमा के दामाद विनय वैकुल ने कहा, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी इसलिए हम उन्हें रात एक बजे के करीब अस्पताल लेकर गए। उनका 3.15 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

अनिल दवे के निधन के बाद डॉ. हर्षवर्धन होंगे नए पर्यावरण मंत्री

नई दिल्ली

अनिल माधव दवे के निधन के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। मौजूदा समय में वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभाल रहे हैं।

आपको बता दें कि आज सुबह ही अनिल दवे का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि 61 वर्षीय दवे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से काफी समय से जुड़े रहे। पिछले साल ही उन्हें पर्यावरण मंत्री का पदभार दिया गया था।

एक साल भी अभी उन्हें इस पद को संभाले नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल दवे के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि वह हमेशा एक समर्पित समाजसेवक के रूप में जाने जाएंगे। मोदी ने कहा कि अनिल दवे का जाना उनके लिए निजी क्षति है।

अनिल दवे ने अपना जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया था। नर्मदा बचाओ अभियान से भी वह जुड़े हुए थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें पिछले साल 5 जुलाई 2016 को पर्यावरण मंत्री का पद दिया गया था।

मोदी सरकार के तीन साल में चरम पर रहे अराजकता और भ्रम - शिवसेना

मुंबई

मोदी सरकार को तीन साल होने वाले हैं। पिछले कई दिनों से सरकार पर हमले करने वाली सहयोगी पार्टी शिवसेना ने एक बार फिर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार के तीन सालों में देश में अराजकता और भ्रम पैदा हुआ है और अगर किसी तरह का जश्न मनाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि सरकार को नाराज लोगों, किसानों की मौत और सैनिकों के बलिदान की कोई परवाह नहीं है।

शिवसेना ने कहा कि देश में लोग नाराज हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सैनिक अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं ऐसे में भी कोई अगर सरकार के तीन सालों की सफलता का जश्न मनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो इन मुद्दों को लेकर कोई परवाह नहीं करते।

शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय पेज पर इस तरह की बातों को जगह दी गई है। सामना में आगे लिखा गया कि हजारों करोड़ रुपये स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च कर

दिए गए क्या अभी तक देश साफ हो पाया है? गंगा की सफाई के लिए महंगा कार्यक्रम चलाया गया क्या अभी तक गंगा की सफाई हुई है? शिवसेना ने कहा कि एनडीए ने सरकार का इसलिए समर्थन दिया था कि कालाधन वापस आएगा और गरीब के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी वादा नहीं निभाया गया। सरकार में रहने से पहले वो कहते थे कि पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलेगा लेकिन देश के जवान शहीद हो रहे हैं और सरकार सिर्फ नोटिस जारी कर रही है।

शिवसेना ने सरकार से सवाल किया कि क्या मोदी सरकार को सिर्फ चेतावनी जारी करने के लिए जनता ने वोट दिया।

अब फैसले का इंतजार, तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

नई दिल्ली

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से जारी सुनवाई खत्म हो गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना। इससे पहले बुधवार को संवैधानिक पीठ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि क्या औरतें तीन तलाक को ना कह सकती हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील सिब्बल से चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने पूछा कि क्या महिलाओं को निकाहनामा के समय तीन तलाक को ना कहने का विकल्प दिया जा सकता है। क्या सभी काजियों से निकाह के समय इस शर्त को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर के सवाल पर सिब्बल का जवाब

कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के एक छोटी सी

चिड़िया है, जिस पर गिद्ध अपनी नजरें गड़ाये बैठा हुआ है। समुदाय के घोंसले को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम समुदाय एक विश्वास के साथ कोर्ट आया है। और अपने पर्सनल लॉ, परंपरा और रुढ़ियों के लिए सुरक्षा मांग रहा है। मुस्लिम समुदाय का सुप्रीम कोर्ट पर पिछले 67 वर्षों से विश्वास है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अदालत इस विश्वास के साथ आता है कि उसे न्यायालय मिलेगा तो अदालत को भी याची की भावना को समझना चाहिए। अगर यदि अदालत में कोई तीन तलाक को रद्द कराने के लिए आता तो वो ठीक था, लेकिन अदालत का स्वत: संज्ञान लेना ठीक नहीं है क्योंकि संविधान भी इस विषय पर मौन ही रहा है।

जब सिब्बल ने कहा मुस्लिम समुदाय ले सकता है कठोर रुख

कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर स्वत संज्ञान लेगा तो मुस्लिम समाज कठोर रुख अपना सकता है। मुस्लिम समाज धीरे धीरे तीन तलाक और बहुविवाह को छोड़ रहा है। लिहाजा अदालत को स्वत संज्ञान लेने से बचना चाहिए था, लेकिन अदालत और सरकार के रुख से ये मामला पुनर्जीवित हो सकता है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

महबूबा मुफ्ती से मिले वित्तमंत्री अरुण जेटली, जम्मू-कश्मीर के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

श्रीनगर

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। ये बैठक श्रीनगर के बुक्कार स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई है। जेटली और महबूबा मुफ्ती की इस मुलाकात के दौरान जम्मू-कश्मीर के विकास के विषयों समेत कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है।

जीएसटी परिषद की बैठक के लिए बुधवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचे जेटली ने मुख्यमंत्री के साथ 45 मिनट तक बातचीत की। अधिकारियों ने बैठक के बाद बताया, महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य को मिलने वाले फंड, विशेष रूप से प्रधानमंत्री

विकास योजना के लिए मिलने वाली धनराशि के प्रवाह की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। साथ ही योजना के तहत समय पर धनराशि जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही जेटली ने जम्मू कश्मीर में एक उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा स्थति की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा बलों से विरोधी तत्वों के साथ दृढ़ता से निपटने को कहा, लेकिन मासूम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सेनाधिकारियों ने कहा कि जेटली शाम को यहां पहुंचे और इसके बाद उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें नवनियुक्त रक्षा सचिव संजय मित्रा तथा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

चीन सीमा तक पहुंचा भारत

ड्रैगन को कुछ यूं देगा जवाब

नई दिल्ली

भारत को घेरने की कोशिश में चीन पूरी तरह से जुटा हुआ है। भारत के पड़ोसी मुल्कों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भारी निवेश के जरिए वो दबाव बना रहा है। यही नहीं चीन के सरकारी स्वामित्व वाले अखबार भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, लेकिन चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारत भी पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। भारत एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ आधारभूत योजनाओं पर तेजी से काम जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमांत गांव दुक्तू तक सड़क मार्ग का निर्माण कर भारत अब चीन को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि किसी भी चुनौती का सामना करने

भारत एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ आधारभूत योजनाओं पर तेजी से काम जारी है

के लिए भारत सरकार तैयार है।

दुक्तू के जरिए चीन पर नजर

11 हजार फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए पहले सोबला से पहाड़ की पगडंडियों पर 46 किमी की दूरी तय करनी पड़ती थी। दुक्तू गांव चीन की ज्ञानिमा मंडी के करीब है। दुक्तू गांव तक पहुंचने के लिए न्यू सोबला-दारमा मार्ग को बनाने में

भारतीय इंजीनियरों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों के बड़ी कामयाबी दिलाई जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि तिब्बती मंडी ताकलाकोट के बाद चीन ने ज्ञानिमा मंडी के पास सामरिक ठिकाना बना रखा है।

भारतीय इंजीनियरों का कमाल

पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा के करीब एक गांव बिदांग है, लेकिन इस गांव में अब कोई नहीं रहता है। हालांकि अब यहां कि जनसंख्या शून्य है। बिदांग से पहले दांतू, तिदांग, मार्चा और सीपू में आबादी रहती है। दुक्तू गांव तक जिस कठिन हालात में सड़क बनाई गई है, वो भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। 20 से 25 दिनों में वाहनों के जाने के लिए कच्ची सड़क बन गई। सीपीडब्ल्यू के इंजीनियरों का कहना है कि 2013 के आपदा के बाद सड़क बनाना बहुत ही कठिन था। दारमा घाटी के जरिए चीन सीमा तक पहुंचने का सपना 2005 में देखा गया था। लेकिन किसी न किसी वजह से काम पूरा नहीं हो सका। ■ शेष पृष्ठ 2 पर